चरखा विकास संवाद
CHARKHA DEVELOPMENT COMMUNICATION NETWORK
अंक 3, द्विमासिक, मार्च 2005

संपादक की ओर से

दोस्तों
आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर चरखा विकास संवाद का यह अंक हमने उन भारत की उन ग्रामीण महिलाओं को समर्पित किया है जिसने अपनी इच्छाशक्ति के बल पर कई बाधाओं को लांघते हुए अलग मुकाम बनाया है।

समाज और परिवार ने इन महिलाओं को कभी भी शासन-सत्ता चलाने, विकास में भागीदारी निभाने और निर्णय लेने के अधिकार से दूर रखा। जिन महिलाओं ने घर-परिवार और समाज की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाया उसका खमियाजा उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के रूप में उठाना पड़ रहा है।

लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने परिवार और समाज की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गई हैं। पिछले दस सालों में महिलाओं में लेखन क्षमता विकसित करने के लिए हमने जितनी कार्यशालाएं की है उसमें हमारा अनुभव यही रहा है कि ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है जिनमें अदम्य साहस भरा है और जो संचार माध्यमों की मदद से सामाजिक बदलाव लाना चाहती हैं।

बीते महीने ग्रामीण महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित दो दिनों की कार्यशाला के लिए मेरा पटना जाना हुआ। वहां मुझे यह देखकर काफी ताज्जुब हुआ कि सभी महिलाएं अपने मुद्दों के प्रति काफी जागरूक थीं और उसका समाधान चाहती थीं। उस समय विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी इसलिए महिलाओं ने खुद को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। इसकी बानगी देखिए कि उन्हें उनका विधायक कैसा चाहिए? जो भ्रष्ट न हो, जो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझें और उन्हें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए, जो जात-पात और छूआछूत को न माने। हमने जब पूछा कि आप अपने क्षेत्र की कुछ ऐसी समस्याएं बताएं जिसपर अपने विधायक का ध्यान खींचना चाहती हों, तो उन सब का एक साथ जवाब आया कि दहेज, दहेज हत्या, महिलाओं के प्रति होने वाले अन्य अपराध, शराबखोरी, शिक्षा और बेरोजगारी ऐसी समस्या है जिनसे उन्हें आए दिन जूझना पड़ता है। वहां मौजूद सभी महिलाओं ने कहा कि हम ऐसे ही व्यक्ति को अपना विधायक बनाएंगे जो हमें इन समस्याओं से निजात दिला सके।

महिलाओं का यह उत्साह और उनकी रूचि देखकर हमें लगा कि ग्रामीण पृष्ठीूमि से आई ये महिलाएं विकास संवाद के महत्व को समझ सकती हैं और उसका इस्तेमाल भी बहुत बढ़िया ढंग से कर सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम

आशा जाहिर करते हैं कि विकास संवाद महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और उनकी आवाज नीति निर्माताओं तक पहुंचाने का काम हम अनवरत जारी रखें।

उत्तर-पूर्वी राज्यों के पत्रकारों की कार्यशाला

उत्तरपूर्वी राज्यों के पत्रकारों के लिए जनवरी में तीन दिनों की कार्यशाला हुई जिसमें चरखा ने भी अपनी भागीदारी निभाई। इस कार्यशाला का मकसद मुख्यधारा मीडिया को उत्तरपूर्वी राज्यों के प्रति संवदेनशील बनाना था। कार्यशाला में चरखा ने उत्तरपूर्वी राज्यों की तरफ एक बार फिर से रूख करने की योजनाओं का खुलासा किया ताकि सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया के साथ अच्छे संबंध विकसित हो और वहां के मुद्दों को उठाया जाए। चरखा ने स्थानीय मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उत्तरपूर्वी राज्यों के मुद्दों को मुख्यधारा मीडिया तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता जताई।

बालिका मेला

उरमूल सेतु संस्था ने 24 फरवरी से 25 फरवरी तक लूणकरनसर में बालिका मेले का आयोजन किया गया। चरखा के प्रतिनिधियों ने भी इस मेले में हिस्सा लिया। पंचायती राज और महिला और बाल विकास के मुख्य मुद्दे पर केंद्रित इस मेले में तकरीबन 1500 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। गांवों में बने किशोरी प्रेरणा मंच की बालिकाओं को पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी देने के लिए इस मेले में उन्हें सरपंच और वार्ड पंच की चुनाव प्रक्रिया से गुजारते हुए उन्हें पंचायती राज व्यवस्था का व्यवहारिक ज्ञान और जानकारी बढ़ाने का प्रयास किया गया। मेले के पहले तीन दिनों में पंचायत बॉडी की बैठक, स्थाई समितियों का गठन, वार्ड सभा में किशोरी बालिकाओं और महिलाओं की समस्याओं की पहचान कर वार्ड वार नियोजन, ग्रामसभा का आयोजन कराना और प्रस्ताव पारित कराना जैसी गतिविधियां सीखाई गई। अंतरराष्ट्रीय संस्था प्लान इंटरनेशनल और सेव द चिल्डर्न फंड के आर्थिक सहयोग से इस मेले का आयोजन किया गया।

ग्रामीण विकास और मीडिया संवाद

गांवों में सूचना पहुंचाने और मीडिया को गग्रमीण मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था ने फरवरी में दो दिवसीय बैठक हैदराबाद में आयोजित किया इस बैठक में सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और जाने-माने पत्रकारों ने हिस्सा लिया।1 चरखा के अध्यक्ष शंकर घोष ने भी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई।

कार्यशालाएं

रांची, झारखंड में क्षमता संवर्धन कार्यशाला, दिसंबर, 2004

चरखा ने अपने स्थानीय सहयोगी मंथन युवा संस्थान के समन्वयन से रांची के अनगड़ा ब्लाक में में चल रहे सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए दिसंबर, 2004 में तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इस कार्यशाला में ऑल इंडिया रेडियो, रांची से श्री ओलीमिंज (एंकर/रेडियो जॉकी), सुश्री ओपल (स्क्रिप्ट लेखिका) तथा ऑल इंडिया रेडियो जम्मू एवं कश्मीर से ध्वनि अभियंता श्री सुबोध कुमार ने रेडियो कार्यक्रमों को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी टिप्स बताए। प्रतिभागियों ने आने वाले रेडियो कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा की।

पटना, बिहार में दो दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला, जनवरी, 2005

इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य जमीनी महिला कार्यकर्ताओं की लेखन क्षमता का विकास करना तथा उनके मुद्दों को बेहतर ढंग से मीडिया के जरिए लोगों के सामने प्रस्तुत करना था। यह कार्यशाला मूल रूप से जमुई, बिहार में हुई ऐसी ही कार्यशाला के फालोअप के बतौर आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में बिहार के भिन्न जिलों से विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय 24 महिलाओं, छात्रों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। उन्हें दीवार अखबार निकालने के अलावा संचार क्षेत्र के अन्य पहलुओं की जानकारी दी गई। इन प्रतिभागियों को चरखा के स्रोत व्यक्तियों मसलन नई दिल्ली से जनसत्ता की वरिष्ठ उप संपादक सुश्री नीलम गुप्ता, दैनिक हिंदुस्तान की सहायक संपादक, सुषमा वर्मा, पटना में राष्ट्रीय सहारा की संवाददाता व वरिष्ठ पत्रकार सुश्री निवेदिता झा, हिंदुस्तान की स्थानीय संवाददाता पूनम के अलावा चरखा से प्रतिभा ज्योति तथा इंद्राणी डे ने लेखन व संवाद कौशल की जानकारी दी।

रायपुर, छत्तीसगढ़ में चार दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला, फरवरी, 2005

इस कार्यशाला का उद्देश्य सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा पत्रकारिता के छात्रों में मीडिया की समझ बढ़ाना तथा उनमें लेखन व संचार क्षमता का विकास करना था। इस चार दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभागियों को चरखा के स्रोत व्यक्तियों मसलन, दैनिक जागरण के नगर-संपादक श्री निकष परमार, हरि भूमि के उप संपादक, श्री निर्मल साहू, हिंदुस्तान की संवाददाता सुश्री इरा झा, रूपांतर की निदेशक सुश्री इलीना सेन के अलावा चरखा की सहायक संपादक सुजाता राघवन तथा वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं कार्यशाला के समन्वयक बाबा मायाराम ने लेखन प्रशिक्षण दिया। इस कार्यशाला के दौरान 34 प्रतिभागियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए राजिम तथा नयापारा कस्बों में भेजा गया, उन्होंने स्थानीय मुद्दों मसलन आजीविका, जलनीति, कृषि व शिक्षा पर लेख/फीचर तैयार किए तथा दीवार अखबार निकालने में उनका इस्तेमाल किया।

उत्तर-पूर्व के पत्रकारों का सम्मेलन, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली

चरखा ने जनवरी में गांधी शांति प्रतिष्ठान में उत्तर-पूर्व पत्रकार संघ की ओर से आयोजित 'राष्ट्रीय मीडिया में उत्तर-पूर्व की खबरों की बढ़ोतरी के लिए संवेदनशीलता बढ़ाना' विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में भागीदारी की तथा जानकारी दी कि चरखा उत्तर-पूर्व में लोकतंत्र के चौथे खंभे की मजबूती तथा जमीनी लोगों की समस्याओं तथा सफलताओं को मुख्यधारा मीडिया में लाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। इस कार्यशाला को उद्देश्य राष्ट्रीय मीडिया में उत्तर-पूर्व के मुद्दों को तरजीह देना था। चरखा को उम्मीद है कि इस पहल से उत्तर-पूर्व के पत्रकारों से उसके संबंध और प्रगाढ़ होंगे तथा वह प्रभावशाली ढंग से वहां को मुद्दों को उठा पाएगा।

उरमूल सेतु संस्थान की ओर से बालिका मेला का आयोजन, लूणकरणसर, राजस्थान, फरवरी 2005

उरमूल सेतु संस्थान ने अपने लूणकरणसर परिसर में पांच दिवसीय, बालिका मेला का आयोजन किया है। इसमें लूणकरणसर के आसपास के 70 गांवों से करीब 1500 बालिकाएं भागीदारी कर रही हैं। इस बालिका मेला का मकसद बालिकाओं की समस्याओं, सफलताओं पर चर्चा करनी है तथा उनके जीवन से संबंधित भिन्न उपयोगी जानकारियां उन्हें मुहैया करानी है। इस बार बालिका मेला का विषय है 'पंचायती राज, महिला तथा बालिका विकास', इसके तहत बालिकाओं को पंचायती राज व्यवस्था तथा उसके भिन्न विकासात्मक पहुलओं से अवगत कराना है, जो महिलाओं तथा बालिकाओं को प्रभावित करते हैं। इस मेले में देश के भिन्न भागों से संगठनों, संस्थाओं के अलावा पंचायती राज, स्वास्थ्य, महिला अधिकार, बाल अधिकार, कृषि, सूचना का अधिकार तथा विज्ञान आदि विषयों पर सक्रिय स्रोत व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया है।

संविधान के 73वें संशोधन में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में मिले आरक्षण के चलते गांव-देहात में बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायत समिति की सदस्य और अध्यक्ष बनीं और बैठकों में हिस्सा लेने और उन्हें अपनी आवाज उठाने का मौका मिला। महिलाओ को पंचायत में आरक्षण मिलने के बाद पुरूषों ने नाक-भौं सिकोड़ते हुए उनकी क्षमता पर संदेह दिया लेकिन अपनी प्रतिभा, सूझबूझ और कर्तव्यपरायणता के चलते कई महिलाओं ने इस धारणा को बदल दिया और समाज के लिए मिसाल बन गई। हमारे सामने भी ऐसे दो उझहरण है:

पुरूषों के आरोप ने बढ़ाई हिम्मत

अपने पिता की उम्र के पुरूष के साथ ब्याह दी गई वीणा देवी 16 साल में ही विधवा हो गई। सामंतवादी प्रभाव वाले बिहार के नवादा जिले की एक छोटी सी पंचायत में एक कामयाब मुखिया बनकर उन्होंने विकास की जो कहानी गढ़ी है वह महिलाओं को कमतर आंकने वालों की धारणा बदलने के लिए मजबूर करती हैं।

नवादा प्रखंड के लहरपुर पंचायत की मुखिया बनने से पहले वीणा ने बहुत दुख भरे दिन बिताए हैं जिसे याद करके आज भी उसके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। कमसिन उम्र में उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से हुई तो उनपर विपत्ति का पहाड़ टूट गया। वे जब ससुराल पहुंची तो पता चला कि वे अपने उम्र के दो बेटों की मां है। पति ने कभी उनके भावनाओं की कद्र नहीं कि तो सास-ससुर ने कभी बहू का दर्जा नहीं दिया। नन्हें हाथों से घर के तमाम काम निबटाते और तरह-तरह की यातना को सहते-सहते वे बड़ी होने लगीं। जब तब वे शादी का मतलब समझतीं तब तक उनके पति की मौत हो गई।

पति की मौत के बाद वीणा पर अपने तीन बेटों, देवर और सास-ससुर की जिम्मेदारी आ गई। घर के किसी पुरूष के न कमाने से आमदनी का कोई जरिया नहीं था इसलिए उन्हेांने अपने घर में एक किराएदार रख लिया ताकि किराया से ही घर का खर्चा चलाया जा सका। लेकिन किराएदार के रूप में जो युवक उनके घर में रहने आया वह एक खूंखार अपराधी था। उसने घर में रहने के एवज में किराया देने से मना कर दिया। इस तरह करीब एक साल बीतने पर जब वीणा ने उससे फिर किराए की मांग की तो उसने गाली-गलौज करना शुरू कर दिया और अपनी बंदूक निकालकर उन्हें और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। हार कर वह वहां के स्थानीय महिला नेताओं से मिली और उनके सहयोग से किसी तरह उस किराएदार से किराया साल भर का किराया वसूला और उसे घर खाली करवाने में भी सफल हो गई।

विधवा होने के बाद डरी सहमी रहने वाली वीणा इस घटना के बाद से मुखर हो गई।। धीरे-धीरे उन्हेंाने खुद को सामाजिक कार्यो से जोड़ लिया और महिलाओं में सामाजिक जागरूकता फैलाने का काम शुरू कर दिया। खुद भाग-दौड़कर अपने गांव के 25 जरूरतमंदों को इंदिरा विकास योजना के तहत घर दिलवाया। दसरअसल उनके प्रयासों के चलते ही लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था और महिलाएं अपने स्वास्थ्य और ज्यादा बच्चे न पैदा करने जैसे मसलों पर खुल कर बात करने लगी थीं।

हालांकि वे राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं रखती थीं लेकिन जब पंचायत चुनाव होने की घोषणा हुई तभी से गांव की महिलाओं ने उन पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाया। महिलाओं की जिद के आगे वे झुक गई। वे अनारक्षित सीट से चुनाव के लिए मैदान में खड़ी हुई और जीत हासिल की।

वे कहती हैं कि मेरे चुनाव लड़ने पर पुरूषों ने नाक-भौं सिकोड़े। उन्हें इस यह कसक है कि तीन साल के भीतर ही उन्होंने विकास के कई ऐसे काम कराए जो बीते सालों में नहीं हुआ बावजूद इसके उनके प्रति पुरूषों का असहयोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।

चुनाव जीतने के बाद वीणा ने सबसे पहले विधवा पेंशन, अन्नपूर्णा योजना और अन्त्योदय योजना का लाभ जरूरतमंदों को दिलाने पर ध्यान दिया। सब को साफ और स्वच्छ पानी मिले यह उनकी प्राथमिकता थी इसलिए गांव में कई हैंडपंप लगवाए। गांव में सड़क बनाने के लिए कई लोगों ने मुफ्त में अपनी जमीन दे दी लेकिन सड़क निर्माण में लगने वाले खर्च की राशि अभी तक पंचायत नहीं पहुंची थी। वे बार-बार प्रखंड कार्यालय तक दौड़ती लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने एक दिन ग्राम सभा की बैठक में यह सुझाव रखा कि यदि हम सड़क बनाने के लिए केवल सरकार पर निर्भर रह गए तो इस काम में अभी बहुत देरी हो सकती है इसलिए यदि गांव का हर आदमी कुछ अर्थदान और श्रमदान करे तो इस काम को आसान बनाया जा सकता है। उनकी कोशिश और गांववालों की लगन का नतीजा यह हुआ कि दो महीने के भीतर गांव में एक पक्की सड़क तैयार हो गई।

महिला प्रतिनिधि होने नाते मुखिया अपने गांव की अन्य महिलाओं की तकलीफों से भी अच्छी तरह वाकिफ थीं। डॉक्टर के अभाव में उन्होंने गर्भवती महिलाओं और बच्चों की मौत होते देखा था इसलिए पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने और 24 घंटे एक डॉक्टर की मौजूदगी की मांग लेकर प्रखंड कार्यालय पर अकेले धरने पर बैठ गईं। अपने मुखिया की हिम्मत बढ़ाने के लिए गांव की अन्य महिलाएं भी अपने-अपने बच्चों को लेकर इस धरने में शामिल हो गई। इसका नतीजा यह कि उनकी सभी मांगें मान ली गई और उसके बाद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हुलिया ही बदल गया। उनके नेतृत्व ने महिलाओं को स्वंय सहायता समूह चलाने का आत्मविश्वास दिया और आज इस पंचायत में कई स्वंय सहायता समूह सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। वीना देवी भी आंखों में बस अब एक ही सपना है कि उनके गांव के हर आदमी के पास एक पक्का मकान हो और कोई बच्चा बिना पढ़े न रह जाए।

देश की पहली हाईटेक महिला सरपंच

वह जब अपने गांव में बहू बनकर आई थी तो बड़ी खामोश रहती थीं लेकिन जब क्षेत्रीय मीडिया ने उन्हें हाईटेक सरपंच का दर्जा दिया तो अब उनके दबंग व्यक्तित्व और कामकाज की बड़ी चर्चा हो रही है। मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा ग्राम पंचायत की एकता जायसवाल अब अपने क्षेत्र के लोगों की आंखों का तारा है। यह जूझारू और युवा सरपंच जब 2000 में आरक्षित पद से चुनाव में खड़ी हुई तो गांव के बड़े-बुजुर्ग सकते में थे। उन्हें लगा गांव की नई बहू पंचायत कैसे संभाल सकती है? उनकी असीमित कर्तव्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता के चलते नई दिल्ली स्थित इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने उन्हें देश की पहली हाईटेक और विशिष्ट महिला सरपंच होने का गौरव प्रदान किया है।

पंचायत पद संभालते ही इस युवा सरपंच ने सबसे पहले गांव में बालिका शिक्षा की कमी दूर करने का बीड़ा उठाया। एकता ने सबसे पहले गांव में कई स्कूल खुलवाए और घर-घर जाकर माता-पिता को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। वे लगातार ग्रामसभा की बैठक करती रही और वहां मौजूद महिलाओं को बारीकी से बेटियों को पढ़ाने के फायदे गिनाती। हालांकि उनकी पंचायत की ज्यादतर महिलाएं आसपास के सोयाबीन के खेतों में काम करती हैं इसलिए वे ग्रामसभा की बैठक में नहीं आ पाती लेकिन एकता उनके घर जाकर या खेतों पर जाकर ही उन्हें बालिका शिक्षा का महत्व समझाती। उनकी कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि अब उनके पंचायत में बालिका शिक्षा की दर आश्चर्यजनक ढंग से 75 फीसदी हो गई है। सरपंच ने भागदौड़ करके गांव में स्कूल तो खुलवा दिया लेकिन गांव में अंग्रेजी के शिक्षकों की भारी किल्लत थी। वह अंग्रेजी में एमए है इसलिए उन्होंने खुद ही कक्षाओं में जाकर अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया।

अम्लाहा ग्राम पंचायत पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है। जहां पहले सूचना और संचार के कमतर साधन और कुछ ही लोगों तक उपलब्ध थे वहां कंप्यूटर और इंटरनेट के आने से लोगों मे अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। पंचायत भवन में कंप्यूटर आने से जहां पंचायत के कामों में सहूलियत हुई है वहीं गांव के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। दरअसल पहले यहां के किसान औने-पौने दामों में अपने फसल बेच दिया करते थे लेकिन इंटरनेट होने से सरपंच की मदद से वे बाजार का भाव जान लेते हैं। इससे यहां के किसान धीरे-धीरे आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगे हैं। जब पंचायत का काम नही हो रहा होता है तब सरपंच खुद गांव के बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखाती है। उन्होंने सामुदायिक विकास योजना, स्वंय सहायता समूह, बालिका शिक्षा, सार्वजानिक शौचालय बनाने के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। इस ग्राम पंचायत में लोगों को सूचना के अधिकार की तहत सारी सुविधाएं कंप्यूटर से मुफ्त ही मुहैया होती है।

पंचायत में महिला प्रतिनिधि होने का फायदा यहां की महिलाएं खूब उठा रही है। सरपंच की कोशिशों से स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भनिरोधक गोलियां, टीके और प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सुविधाएं मुहैया हो रही है। जाहिर है जनसंख्या नियंत्रण रखने के अपने सरपंच की कोशिशों पर उन्हें गर्व महसूस होता है।

एकता अपने इलाके की दबंग सरपंच मानी जाती है क्योंकि उन्होंने पुरूषों के धूम्रपान और शराब पीने पर सख्त पाबंदी लगा दी है शराब पीकर पत्नी को पीटने वाले पुरूषों से वे ग्राम सभा की बैठकों में पहले तो ढ़ेरों सवाल-जबाव करती है और उसके बाद सबके सामने पत्नी से माफी मांगने को कहती है। शर्म के मारे वह पुरूष दुबारा अपनी पत्नी को नहीं पीटने और शराब नहीं पीने की वादा कर ही लौट पाता है।

अमलाहा पंचायत के पुरूष और बड़े से बड़े अधिकारी उनसे खौफ खाते हैं लेकिन फिर भी एकता इस बात से इंकर नहीं करती कि पंचायत में विकास कार्य करवाने के लिए उन्हें कई बार बड़े अधिकारियों को रिश्वत तक देना पड़ा है। वे मानती हैं कि महिला सरपंचों की सबसे बड़ी दिक्कत रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों से अपना काम करवाने में आती है क्योंकि जहां एक

तरफ पंचायत में विकास कार्य करने का दबाव होता है वहीं दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारियों की पैसे देने की मंजूरी होती है। हालांकि एकता ऐसे प्रशासनिक मशीनरी में खुद को सहज नहीं मानती फिर भी उनके उज्जवल खाते में उनकी अगुआई में गांव में विकास कार्यो की उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी कराना दर्ज है। जाहि है अपने काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता औ दृढ़ता से वे दूसरों के लिए मिसाल बन गई है।

चरखा विकास संवाद
तीसरा अंक, माच 2004

महिला और मीडिया

किरण अग्रवाल

मीडिया में महिलाओं की दो तरह की भूमिका है। एक तो वह जो जिसने मीडिया को अपने कैरियर के रूप मे अपनाया है और दूसरा वह जिसका इस्तेमाल मीडिया अपने फायदे के लिए करता है। मीडिया महिला सशक्तिकरण, लैंगिक भेदभाव दूर करने और महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने में एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है लेकिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी वह भूमिका सफलतापूर्वक नहीं निभा पा रहा है।

मीडिया में महिलाओं की नकारात्मक छवि दिखाया जाना तकलीफदेह है। दहेज के लिए हत्या, बलात्कार और छेड़खानी जैसी घटनाएं सनसनीखेज बना दी जाती है। जहां पीड़िता के नाम और पहचान छुपाए जाने की जरूरत होती है वहां इस तरह से घटना की चर्चा की जाती है कि पाठक आराम से उस पीड़िता को पहचान लेते हैं। अखबारों का पेज तीन में उसी महिलओां की ज्यादा चर्चा करती हैं जो अभिजात्य घराने की है और उनका हर काम मीडिया को प्रभावित करता है। टीवी पर दिखाये जाने वाले धारावाहिकों में महिला चरित्र को या तो खलनायिका के तौर पर परिवार को तोड़ने की साजिश करता दिखाया जाता है या भगवान के सामने अपने परिवार और पति की मंगलकामना करते हुए। इस तरह महिलाओं की जो छवि बनाई जा रही है उसका प्रभाव आनेवाली पीढ़ी पर पड़ता है। मीडिया का व्यापारीकरण ने महिलाओं की यह छवि बनाई है जिससे उत्पाद को आसानी से बेचा जा सके। इस तरह उत्पादन बेचने के लिए मीडिया उनके अलग-अलग रूपों का सहारा लेता है।

आज का मीडिया केवल 'फेयर एंड लवली', शहरी और पढ़ी-लिखी महिलाओं का हिमायती है।उसके दायरे में भारत के गांवों की वह महिला या बच्ची नहीं है जो दिन-भर खेतों में काम करती है, या किसी सामाजिक संस्था से जुड़कर अपने गांव और क्षेत्र के विकास के लिए काम करती है और व्यक्तिगत या सामाजिक सभी तरह की चुनौतियों का डट कर सामना करती है।

मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है लोगों को सूचनाएं देना और यदि मीडिया अपनी यह जिम्मेदारी गंभीरता से लेता है तो इसके माध्यम से महिलाओं को जागरूक बनाने, महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाने और सशक्त करने का काम किया जा सकता है। इस तरह मीडिया को संवेदनशील और जिम्मेदार बनाने की चुनौती हमारे सामने बनी हुई है। पारंपरिक और आधुनिक मीडिया का इस्तेमाल करते महिलाओं की नकरात्मक छवि को दूर किया जा सकता है इस दिशा में कोशिश जरूर होनी चाहिए।

(लेखिका मानव संसाधन मंत्रालय के महिला और बाल कल्याण विभाग में सचिव रह चुकी हैं।)

मातृत्व या सजाए-मौत

नारायणी के.

बेटा पैदा करने के बढ़ते सामाजिक दबाव ने महिलाओं को अपनी जान तक जोखिम में डालने को मजबूर कर दिया है। बेटे की चाह में वे अपने गर्भ में पल रही कन्या शिशुओं की जान लेने के लिए जानलेवा तरीकों पर अमल करने लगी हैं। एक महिला के लिए मातृत्व के सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है लेकिन आज ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही हैं, जिनके लिए मातृत्व लगातार मौत की वजह बनती जा रही है।

कहने को तो महिला की कोख पर उसका अपना अधिकार होता है लेकिन तीसरी दुनिया की महिलाओं के कोख का अधिकार उनके पति और सास के हाथों में होता है। पति जैसे चाहे जितनी बार चाहे उसे गर्भपात कराना होता है। चाहे यह प्रक्रिया गिरती-मरती सेहत के मद्देनजर उसके लिए जानलेवा ही साबित क्यों न हो। यानि एक महिला की सेहत की देखरेख का अधिकार भी पुरूषों के दायरे में चला गया है। हालांकि देश के सभी हिस्सों में गर्भपात की घटनाएं आम है लेकिन उत्तरप्रदेश के मैनपुरी जिले में जो हो रहा है वह दिल दहला देने वाला है।

मैनपुरी और उसके आसपास के इलाकों में गर्भपात करने के लिए अप्रशिक्षित दाईयां सफाई की बत्ती का इस्तेमाल कर रही है। गर्भपात, वह भी इसलिए ताकि गर्भ में पल रही शिशु कन्या से निजात मिल सके। जड़ी-बूटियों से बनी इस छड़ी को गर्भपात कराने वाली महिला के शरीर में डाला जाता है। भयंकर दर्दनाक प्रक्रिया के बाद शिशु सिकुड़ कर बाहर आ जाता है। आमतौर पर शिशु के बाहर आते समय गर्भपात करने वाली दाई वहां मौजूद नहीं होती है जबकि इस दौरान काफी खून बहता है।

देश के विभिन्न भागों में गर्भपात क्लीनिक चलाने वाली संस्था परिवार सेवा संस्थान के मुताबिक अप्रशिक्षित दाईयां जिस सफाई की बत्ती का इस्तेमाल करती हैं वह न तो वैज्ञानिक आधार पर बनाई गई हैं न ही सफाई के लिहाज से उपयुक्त है। इससे महिला को संक्रमण होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है जो उसकी मौत का कारण बन जाता है। संस्थान के मुताबिक सफाई की बत्ती पर मलेरिया की दवा सहित कई खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जाता है।

गर्भ में पल रहे शिशु के विकास और शरीर के आंतरिक हिस्सों के बारे में जानकारी के लिए 1980 में अल्ट्रासाउंड मशीनों का चलन शुरू हुआ तो कन्या भ्रूण हत्या की कुप्रथा ही शुरू हो गई। जिससे दिनों-दिन महिलाओं की संख्या कम होने लगी है। हालांकि सरकार ने 1994 में प्रसव पूर्व जांच तकनीक (विनियोग और दुरूपयोग निवारण) कानून बनाया जिसमें अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों में लिंग परीक्षण को अपराध घोषित किया है, बावजूद इसके परिवार नियोजन के नाम पर गर्भपात कर अभी भी देश के सभी हिस्सों में धड़ल्ले से सरकारी नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ायी जा रही है।

मैनपुरी और उससे सटे ग्रामीण इलाकों में महिला और उसके परिवारवालों के लिए सफाई की बत्ती का इस्तेमाल गर्भ में पल रही कन्याभ्रूण से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका बनता जा रहा है। हैरत की बात ये है कि बेटे की चाहत में महिलाएं खुद खतरे उठाने से नहीं हिचकती हैं। वैसे भी मातृत्व मृत्यु दर में इन मौतों की कोई गिनती नहीं की जाती।

मैनपुरी जिले के झंझाली ब्लॉक के गांव किरतपुर की अनीसा का मामला लीजिए। छह बच्चों की मां 25 वर्षीय अनीसा की इस साल फरवरी में गर्भपात के दौरान मौत हो गई। गर्भावस्था के पांचवें महीने में जब उसके परिवार वालों को पता चला कि उसकी कोख में एक कन्याभ्रूण पल रहा है तो सफाई की बत्ती से उसका गर्भपात कराया गया। लेकिन खून न रुकने से उसकी मौत हो गई। इसी गांव की 32 वर्षीय सरला अपने गर्भपात के लिए दो बार यह तरीका आजमा चुकी हैं लेकिन वह उन भाग्यशालियों में से है, जो इस दर्दनाक प्रक्रिया के दौरान बच जाती हैं। यह पूछे जाने पर कि वे जिला अस्पताल क्यों नहीं गई, उनका जवाब था कि अस्पताल यहां से बहुत दूर है इसलिए वे वहां नहीं जा सकती हैं।

इसी गांव से सटे ठाकुर बहुल झंझोली गांव में भी सफाई की बत्ती से बड़े पैमाने पर अजन्मी कन्याओं को मारा जा रहा है, साथ ही मांए भी अपनी जान गंवा रही हैं। गांववाले बताते हैं कि मार्च में गर्भपात के बाद दो औरतों की मौत हो गई। बत्ती का इस्तेमाल केवल मैनपुरी जिले में ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी जिलों में भी खूब किया जा रहा है। फैजाबाद के प्राथमिक

स्वास्थ्य केंद्रों पर हर सप्ताह लगने वाले बांध्यीकरण शिविरों में आने वाली ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भपात की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजर चुकी हैं। सफाई की बत्ती का इस्तेमाल केवल अजन्मी लड़कियों को मारने के लिए ही नहीं बल्कि अविवाहित लड़कियों के गर्भ गिराने के लिए भी किया जाने लगा है। बत्ती का एक पूरा बक्सा मैनपुरी और फैजाबाद के कई दुकानों में महज पचास रूपयों में मिल जाता है। ये बत्ती बरेली और कानपुर के छोटे-मोटे कंपनी में बनाए जाते हैं।

अजन्मी कन्याओं के साथ-साथ मांओं को मारने का जो सिलसिला उत्तरप्रदेश के इन जिलों में जारी है उसकी वजह वही है जो आमतौर पर देश के दूसरे राज्यों में हैं। अशिक्षा, बुढ़ापे में अकेले रहने का डर, बेटी के लिए दहेज का दबाव, जागरूकता की कमी, स्वास्थ्य केंद्रो का अभाव और सरकारी लापरवाही, ये ऐसे कारण है जिसके लिए भ्रूण हत्याओं और गर्भपात के दौरान माताओं की मौत का प्रतिशत दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है।

फिरोजाबाद के एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में गर्भपात की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसी जिले के एक स्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम मुनीश कुमारी बताती हैं कि गर्भपात की निकटतम सुविधा एटा जिले में है जो 20 किमी दूर है जहां महिलाओं को जाने में बहुत परेशानी होती है। उनके पति या घर का कोई अन्य सदस्य भी उन्हे दूर के अस्पतालों में नहीं ले जाना चाहते। ऐसे में मजबूरन महिलाओं को गांव के ही अप्रशिक्षित दाईयों से गर्भपात कराना पड़ रहा है। मैनपुरी में केवल बर्नहाल एमटीपी फैसीलिटी में यह सुविधा है, जहां बहुत भीड़ होती है। वैसे जिला अस्पतालों में परिवार नियोजन के लिए गर्भपात कराने की सुविधा है जहां अनुभवी डॉक्टर भी होते हैं लेकिन जानकारी के अभाव और दूरी के चलते महिलाएं इन अस्पतालों में नहीं आती हैं।

अभी पिछले माह तक राज्य की ओर से महिलाओं के लिए चलाई गई परियोजना *सिफ्सा* के कार्यकारी निदेशक रह चुके कपिलदेव का कहना है कि पिछले 11 सालों से दाईयों को प्रशिक्षित नहीं किया गया है जिसका नतीजा महिलाओं को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय भी स्वीकार करता है कि गर्भपात के लिए असुरक्षित तौर-तरीकों के चलन की उसे जानकारी है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि गर्भपात करने के तरीकों को लेकर एक सर्वेक्षण चल रहा है और उसके निष्कर्षो के आधार पर जल्दी ही कोई कानून बनाया जाएगा। आशंका इस बात की है कि कानून के बनने और उसके लागू होने तक सफाई की बत्ती न जाने तब तक कितने महिलाओं के जीवन की सफाई कर देगा। (चरखा)

'मंजिल अभी दूर है'

उषा चौधरी

'1995 में सरपंच बनने पर जब ग्राम सभा की बैठक में मुझे सार्वजनिक तौर पर बोलने के लिए कहा गया तो मैं रो पड़ी। मुझे इस बात की आशंका थी कि कहीं वे मुझ पर किसी तरह का दबाव तो नहीं डालेगें। मैंने हिम्मत करके बोलना शुरू किया-आप सबने मुझे सरपंच बनाया है, इसलिए मुझ पर कोई काम के लिए दबाव मत डालना। ये शब्द अजमेर जिले की मसूदा पंचायत समिति के रसूलापुरा पंचायत की 49 वर्षीय भूतपूर्व सरपंच छग्गी देवी भील के हैं जिसने अपने कार्यकाल में विकास की कई कहानी गढ़ी है। बिना किसी के दबाव में आए उन्होंने अपने कार्यकाल के पांच साल पूरे किए।

यह वाकया 9 साल पहले उनके सरपंच बनने के समय का है। लेकिन आज छग्गी बाई एक सशक्त और मजबूत महिला मानी जाती है। वह राजस्थान में सक्रिय एकल नारी शक्ति संगठन की नेतृत्वकर्ता है और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गई

है। उनके अतीत में झांके तो वही कहानी मिलेगी जो भारत के ज्यादातर महिलाओ के जीवन का हिस्सा है। बचपन में किसी तरह थोड़ा-बहुत पढ़ना लिखना सीख रही थी कि मां-बाप ने एक शराबी आदमी से शादी कर दी। पति रोज दारू पीकर पीटने लगा। इसी बीच तीन बच्चों की मां बन गई। पति का अत्याचार जब बहुत बढ़ गया तो तीनों बच्चों को लेकर भाई के घर चली गई और मजदूरी करने लगी।' यहीं से शुरू होती है छग्गी बाई के सशक्त और जुझारू औरत के रूप में उभरने और अन्य एकल महिलाओं को सशक्त करने की कहानी।

मजदूरी करने जाती छग्गी बाई रोज देखती थी कि अकेली रहने वाली या विधवा महिलाएं तरह-तरह से शोषित और अपमानित हो रही थी। 1995 में गांव वालों के कहने पर वह सरपंच पद के लिए खड़ी हुई लेकिन वहां भी ऊंची जाति के लोगों का दबदबा था। लोकतंत्र की जमीनी इकाई पर भ्रष्टाचार, शोषण और किसी तरह की सुनवाई न देख छग्गी बाई को वो माहौल भी रास नहीं आया। उनके अंदर एकल महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को खत्म करने व उन बुराईयो के खिलाफ लड़ने की इच्छा हो रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां से और कैसे शुरू करे? तभी उन्होंने एकल नारी शक्ति संगठन, जो कि राजस्थान में एकल महिलाओं के साथ काम करता है, के बारे में सुना तो छग्गी बाई के जैसे पंख लग आए।

अब उन्होंने उदयपुर जाकर संगठन से जुड़ने की ठानी। छग्गी बाई बताती हैं कि उस समय मेरे पास उदयपुर जाने का किराया भी नहीं था लेकिन मैंने किसी से पैसा उधार लिया और वहां की संगठन संचालिका जिनी बहन से अजमेर में बतौर संगठन की सदस्य बनकर काम करने की इच्छा जताई। इस पर जिनी को लगा कि शायद मैं इस काम को पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर पाऊंगी। उनकी शंका देखकर मैंने पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करने का वादा किया तो वे मान गयीं। छग्गी बाई जब एक बार इस राह पर चल पड़ी तो उसके बाद पीछे मुड़ कर कभी नहीं देखा।

आज छग्गी बाई अजमेर जिले की 8 पंचायत समितियों में गरीब एकल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संघर्षरत हैं। उनके साथ जिले की 4000 महिलाएं जुड़ी हैं। ये सभी भील, रैगर, दलित, मेघवाल, हरिजन, आदिवासी समुदाय से है। छग्गी बाई व दो अन्य महिलाएं गांव-गांव जाकर बैठकें लेती है और एकल महिलाओं की समस्या का समाधान करती है जहां पर पेंशन, सरकारी सहायता, सामाजिक फैसले, रोजगार संबंधी जानकारियां दी जाती है और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। छग्गी बाई एकल नारी शक्ति संगठन की राज्य कमेटी की सदस्य भी हैं साथ ही संगठन की उपाध्यक्ष भी। गरीब एकल महिलाओं के लिए नीति परिवर्तन हेतु वह कई बार मुख्यमंत्री से भी मिली है। इसी बीच छग्गी बाई ने अपनी दो बेटियों को पढ़ाने के बाद ही शादी की है। एकल महिलाओं के सशक्तिकरण के अलावा छग्गी बाई दारूबन्दी, भ्रष्टाचार रोकने व शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का कार्य भी लगातार कर रही है।

हालांकि यह कहानी छग्गी बाई की है लेकिन आज लाखों एकल महिलाएं देश में इसी तरह का जीवन जी रही है। उनके ऊपर बच्चे पालने की जिम्मेदारी बनी हुई है, क्योंकि पति की मृत्यु होने या फिर पति के अत्याचारों से परेशान होकर वे घर से अलग कर दी जाती हैं या घर छोड़ देती हैं। समाज, परिवार का तिरस्कार पूर्ण व्यवहार, खाने-पीने, ओढ़ने, पहनने में रोक-टोक, चरित्र पर इल्जाम, प्रताड़ना, रोजगार की तलाश में उन्हें कई परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। यह सब इसलिए क्योंकि पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था के कारण हमारे देश में अभी भी एकल महिला को सम्मानजनक दर्जा प्राप्त नहीं है। जबकि पत्नी की मृत्यु होते ही या पत्नी को घर से निकालते ही पुरुष की तुरंत दूसरी शादी कर दी जाती है।

लेकिन छग्गी बाई और एकल नारी शक्ति संगठन की उन 17,000 सदस्याओं ने समाज के इन गलत रीति-रिवाजों व पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता की चुनौती देने की ठानी है। अब वे सब मिलकर अपने विरुद्ध परिस्थितियों का मुकाबला करती है।

छग्गी बाई के मुताबिक 'हम अकेले जरूर हैं लेकिन पूरे राजस्थान की गरीब एकल महिलाएं (संगठन) हमारे साथ है। अब तो कलेक्टर, बी डी ओ भी हमारी बात पहले सुनते हैं। गांवों के सरपंच व मुखिया भी हमारा कहा मानने लगे हैं और ये शक्ति हमारे अन्दर संगठन से आई है।' गांव की अन्य महिलाए व पुरुष अपने गांव में हुए झगड़ों आदि का फैसला कराने छग्गी बाई के पास आते है ।

छग्गी बाई शक्ति की ऐसी चिंगारी है जो बुझ नहीं सकती, बल्कि वह ऐसी ज्योति में बदल चुकी है जो अन्य महिलाओं में चिंगारी जगाएगी। छग्गी बाई जब एकल महिलाओं की बैठकों में जाती है ती उनकी समस्या खत्म करके ही घर लौटती है। कई बार इस प्रक्रिया में तीन से चार दिन भी लग जाते हैं। अब तो इनके बच्चों को भी खूब अच्छी से पता है कि मां घर नही आई, इसका मतलब है कि वह किसी जरूरतमंद महिला के साथ है। बच्चे भी मां के इस कार्य से खुश हैं व मां का पूरा साथ देते हैं। आप उनके घर जाकर देंखें तो पाएंगे कि छग्गी बाई अपने घर में दिन में आधे घंटे भी खाली नहीं बैठ सकतीं। गांव से कोई न कोई बुलाने आ जाता है। हर किसी की कोई न कोई समस्या होती है। रास्ता बताओ, फैसला करो। पास के गांव से भी महिलाएं और यहां तक कि पुरूष भी छग्गी बाई के पास फैसले के लिए आते रहते है। छग्गी बाई कहती है 'अभी मेरा संघर्ष खत्म नहीं हुआ मुझे हर घर में एक छग्गी बाई तैयार करना है जो पुरुष प्रधान समाज से सर उठाकर जी सके।' (चरखा)

समाजिक बदलाव के लिए कॉमिक्स

चरखा सामाजिक कार्यकर्ताओं, पंचायतकर्मियो और महिलाओं को कॉमिक्स और कार्टून बनाने का भी प्रशिक्षण देता है ताकि वे प्रभावशाली और आसान तरीके से मीडिया तक अपनी बात पहुंचा सके। कॉमिक/कार्टून के जरिए चरखा के प्रतिभागी सामाजिक बदलाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं।